उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 3 | अंक 14 | 16-31 दिसंबर 2019 | ₹ 20/-

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की संभावना

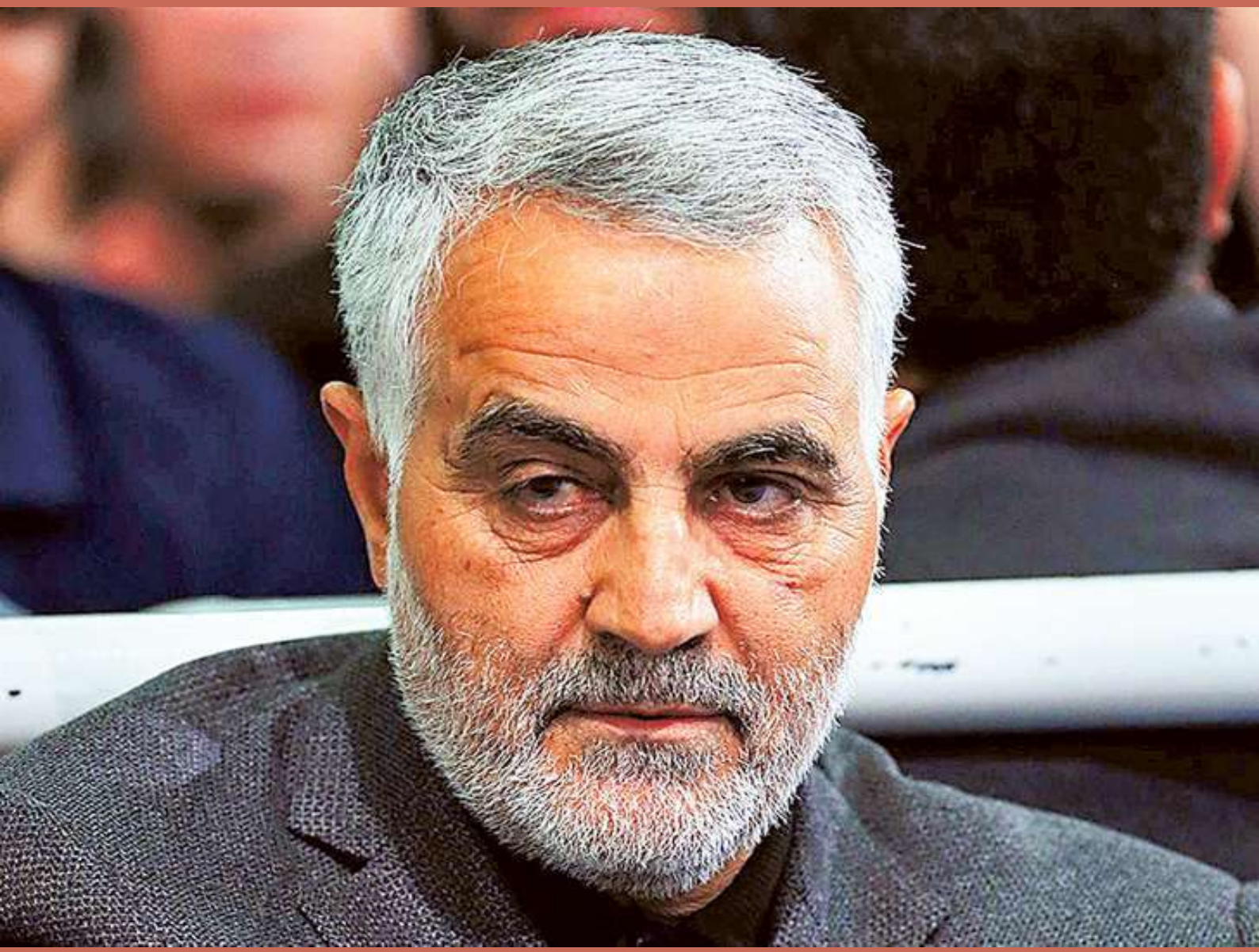

- रामपुर के नवाब परिवार की अरबों की संपत्ति पर विवाद
- ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पथराव
- अमेरिका को भारत के शिया नेता की धमकी
- चेकोस्लोवाकिया में मुस्लिम विरोधी अभियान

भारत नीति प्रतिष्ठान के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

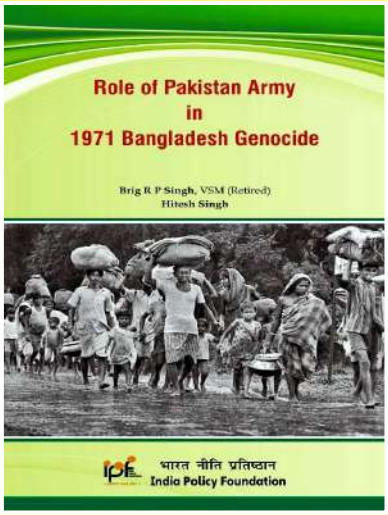

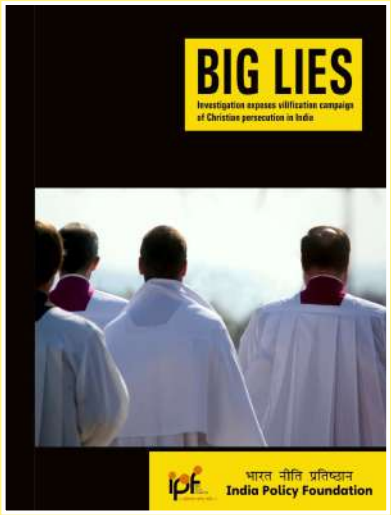

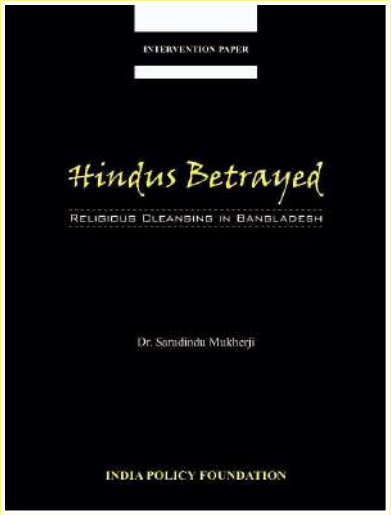

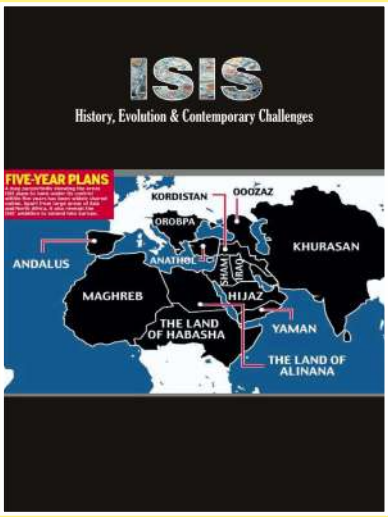

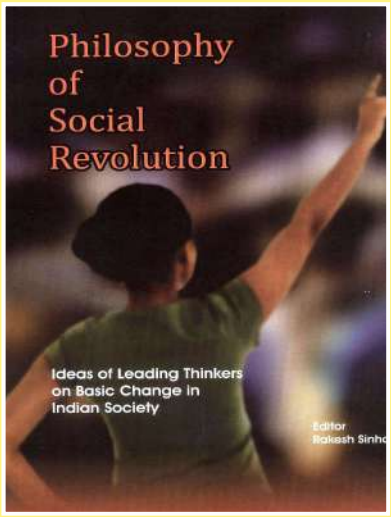

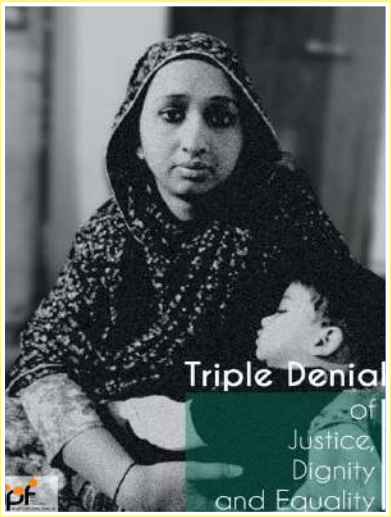

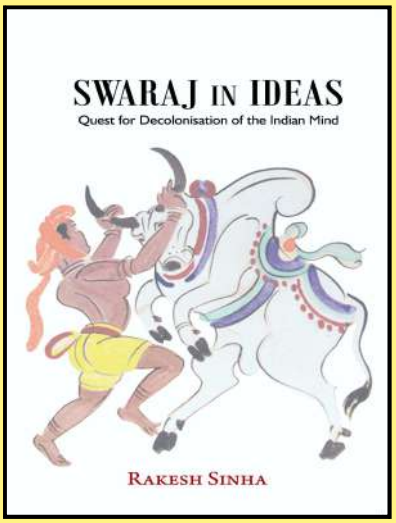

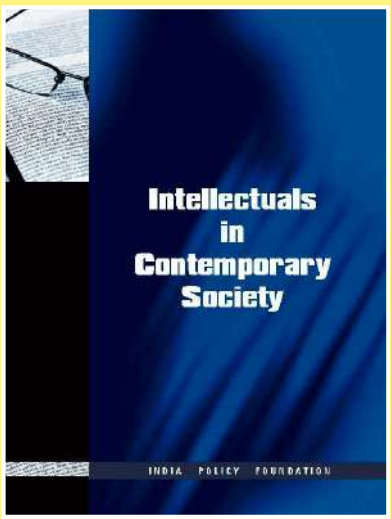

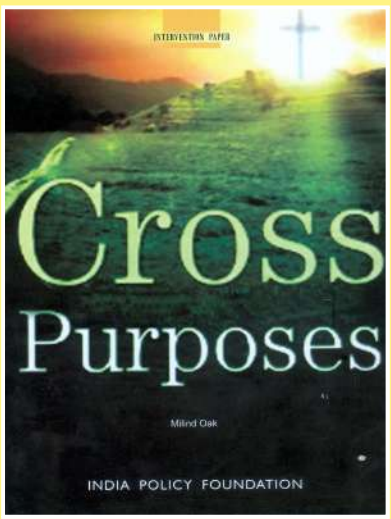

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष - 3 अंक - 14 16-31 दिसंबर 2019

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा *

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

आवरण एवं सज्जा
सूरज भारद्वाज

कार्यालय
**डी–51, प्रथम तल,
हौज खास,
नई दिल्ली–110016**
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए, डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाषित तथा साई प्रिटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 2

राष्ट्रीय

रामपुर के नवाब परिवार की अरबों की संपत्ति पर विवाद 3
नागरिकता कानून के विरोध में गिरफ्तार लोगों को कानूनी सहायता 4
कश्मीर के मामले पर इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी 5
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में चार मुसलमान 7
अयोध्या में मस्जिद के लिए पांच वैकल्पिक स्थान 8
बोगस लाइसेंस का मकड़जाल 9

विश्व

ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पथराव 10
चीन में पांच लाख मुसलमान बच्चे परिवार से अलग 12
पाकिस्तानी मॉडल का हत्यारा भाई सरकार के हवाले 12
चेकोस्लोवाकिया में मुस्लिम विरोधी अभियान 13
सूडान के अधिकारियों को फांसी 13

पश्चिम एशिया

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की तैयारियां 14
आतंकवाद के आरोप में 24 व्यक्तियों को सजा 18
सोमालिया में बम धमाके से 76 मरे 18
सऊदी अरब में अश्लील कपड़े पहनने के आरोप में 200 व्यक्ति गिरफ्तार 19
सैनिक स्कूल पर हमला 19
ईरान में विदेशी ऑयल टैंकर जब्त 20

अन्य

अमेरिका को भारत के शिया नेता की धमकी 21
मुंबई में बकरे काटने पर प्रतिबंध 22
बीबी को बंदरिया कहने पर जुर्माना 22
चारमीनार की लोकप्रियता 23
उत्तर प्रदेश में तीन तलाक का मुकदमा 23
फर्जी आधार कार्ड बनाने पर रोहिंग्या गिरफ्तार 24

सारांश

अमेरिका और ईरान के सम्बन्ध दिन-प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। ईरान का यह आरोप है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः चुनाव जीतने के लिए विश्व को तीसरे युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प के निर्देश पर ड्रोन हमले में ईरान के सबसे लोकप्रिय जनरल कासिम सुलेमानी की अन्य दस व्यक्तियों के साथ हत्या कर दी गई है। कहा जाता है कि अरब जगत को विघटित करने के लिए इस्लामिक स्टेट नामक जो जिहादी खिलाफत बनाई गई थी उसका सफाया करने में सुलेमानी की विशेष भूमिका थी। मुस्लिम जगत की इस्लामिक एकता तार-तार हो चुकी है और यह शिया और सुन्नी गुटों में बंट गया है। अगर खाड़ी देशों में युद्ध की ज्वाला भड़कती है तो उसका प्रभाव समूचे विश्व पर पड़ेगा। जहां तक भारत का सम्बन्ध है उसकी अर्थव्यवस्था पेट्रोल के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण प्रभावित हो जाएगी। पेट्रोल के मामले में भारत अपनी दो तिहाई मांग ईरान और इराक से ही पूरी करता है। एक बात जो कि विशेष रूप से ध्यान देने वाली है वह यह है कि भारत के मुसलमान खुलकर ईरान के समर्थन में सड़कों पर आ गए हैं। इससे निश्चित रूप से सउदी अरब के शासकों को परेशानी होगी जो कि अभी तक भारतीय मुसलमानों को अपनी बपौती माने हुए थे।

उत्तर प्रदेश की प्रमुख मुस्लिम रियासत रामपुर के नवाब परिवार की अरबों की संपत्ति का विवाद गत तीन दशक से चल रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाया था कि रियासती परम्परा के अनुसार सारी संपत्ति का वारिस राजपरिवार का प्रमुख ही होता है इसलिए नवाब परिवार के आठ दावेदारों को इस संपत्ति से वंचित कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ इन वारिसों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि नवाब परिवार की समूची संपत्ति का विभाजन मुस्लिम शरिया के अनुसार किया जाए। इस फैसले के अनुसार अब संपत्ति के सत्रह दावेदार हैं। इनमें से कुछ दावेदार पाकिस्तान जा चुके हैं इसलिए उनके हिस्से की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत भारत सरकार को मिलेगी।

महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली उद्धव ठाकरे सरकार ने चार मुसलमानों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। खास बात यह है कि शिवसेना के इतिहास में पहली बार उसके किसी मुस्लिम विधायक को मंत्री बनाया गया है। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में दस मुस्लिम विधायक विजयी हुए हैं। महाराष्ट्र में इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हाल के चुनाव में उसके दो विधायक चुने गए हैं। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी दो मुस्लिम विधायक विजयी हुए हैं। इससे साफ है कि राज्य के मुसलमानों में मजलिस के साथ-साथ समाजवादी पार्टी का प्रभाव भी बढ़ रहा है।

पाकिस्तान द्वारा सिखों को भारत के खिलाफ भड़काने का जो अभियान चल रहा था उसे हाल ही में एक करारा झटका तब लगा जब मुसलमानों की उत्तेजक भीड़ ने गुरु नानक देव जी के जन्मस्थान ननकाना साहिब स्थित गुरुद्वारे पर हमला कर दिया और उसे क्षति पहुंचाई। इस हमले का कारण यह था कि एक वर्ष पूर्व इस गुरुद्वारे के ग्रंथी की पुत्री को जबरन वहां के मुसलमानों ने उठा लिया था और उसका जबरन धर्मांतरण करने के बाद उससे निकाह रचा लिया। हाल ही में यह मामला जब न्यायालय तक पहुंचा तो पाकिस्तान सरकार ने विश्व भर के सिखों में हो रही इसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इससे चिढ़कर मुसलमानों की भीड़ ने गुरुद्वारे पर धावा बोल दिया और उसे क्षति पहुंचाई। इस घटना की विश्वभर के सिखों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इस पर इमरान खान के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद हमले के आयोजक इमरान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया।

रामपुर के नवाब परिवार की अरबों की संपत्ति पर विवाद

रामपुर नवाब परिवार की अरबों रुपये की संपत्ति जो दशकों से विवाद में उलझी हुई थी अब उसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार उनके वारिसों में बांटने का निर्देश दिया है। इनमें से कुछ वारिस पाकिस्तान जा चुके हैं इसलिए उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (31 दिसम्बर) के अनुसार "पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अब्दुर रहीम खान की पत्नी मेहरुन्निसा की अरबों रुपये की संपत्ति उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौजूद है। मगर यह संपत्ति उन्हें नहीं मिल पाएगी। अब्दुर रहीम खान रामपुर नवाब खानदान के दामाद थे। मेहरुन्निसा आखिरी नवाब रजा अली खान की पुत्री हैं। विवाह के बाद वह पाकिस्तान चली गई। इन दिनों वह अमेरिका में रहती हैं। अब केन्द्र सरकार इसे शत्रु संपत्ति घोषित करने पर विचार कर रही है। रामपुर के नवाब परिवार के पास अरबों रुपये की संपत्ति है। लेकिन इसके बंटवारे को लेकर गत कई दशकों से विवाद चल रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विभाजन के लिए निर्देश जारी किए हैं। जिन व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्देश दिया गया है उसमें 86 वर्षीया मेहरुन्निसा भी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश को शरई कानून के अनुसार नवाब परिवार की संपत्ति के विभाजन के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस संपत्ति को दिसम्बर 2020 तक बांट दिया जाए।"

"जिला न्यायाधीश ने दो वकीलों को इस संपत्ति के बंटवारे के लिए कमिश्नर नियुक्त किया है। एक कमिश्नर कैलाश अग्रवाल के अनुसार नवाब परिवार की संपत्ति खास बाग, लक्खी बाग, बेनजीर बाग और एक दर्जन महलों के साथ-साथ सैकड़ों एकड़ भूमि की है। इसकी कीमत अरबों रुपये बताई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिन लोगों को इस संपत्ति में हिस्सा देने का निर्देश दिया है उसमें 17 भागीदार हैं। उनमें से 16 नवाब परिवार के सदस्य और एक कस्टोडियन हैं। पूर्व सांसद बेगम नूर बानो का कहना है कि मेहरुन्निसा बेगम शादी के बाद पाकिस्तान चली गई थीं और अब वह अमेरिका में रहती हैं तथा काफी वर्षों से वह रामपुर नहीं आई हैं। जिलाधिकारी के अनुसार देश के विभाजन के समय जो लोग विदेश चले गए थे और वहां की नागरिकता ले ली थी उनकी संपत्ति कस्टोडियन की संपत्ति मानी जाती है और इस पर सरकार का अधिकार होता है। रामपुर नवाब परिवार के काफी लोग विदेश चले गए हैं इसलिए उनकी संपत्ति पर सरकार का अधिकार है।"

अखबार-ए-मशरिक (1 जनवरी) के अनुसार न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर कैलाश अग्रवाल ने जिलाधिकारी के साथ मिलकर नवाब परिवार की कुछ संपत्तियों की वीडियोग्राफी की। उन्होनें कहा कि खास बाग 50 एकड़ भूमि में बना हुआ है जबकि 500 एकड़ भूमि इस महल की परिसर की है और इस पर खेती होती है। रामपुर रेलवे स्टेशन पर नवाब साहब का जो रेलवे स्टेशन है वह भी 500 एकड़ भूमि पर स्थित है। इस भूमि की भी वीडियोग्राफी की गई है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों के साथ मिलकर हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि नवाब परिवार की हजारों एकड़ भूमि और अन्य अचल संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाए ताकि बाद में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नवाब के वारिसों में शरा मोहम्मदी के नियमों के अनुसार विभाजित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

टिप्पणी: रामपुर रियासत उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख मुस्लिम रियासत थी। इसकी स्थापना 1733 में नवाब फ़ैजुल्लाह खान ने की थी। इस रियासत पर दस नवाबों का शासन रहा। अंतिम नवाब रजा अली खान थे जिन्होंने 1949 में अपनी रियासत का विलय भारत में किया था। उनकी मृत्यु 1966 में हो गई थी। उनकी संपत्ति पर उनकी संतानों ने दावा किया था जो कि आठ भाई-बहन थे। शाही खानदान की

परम्परा के अनुसार जो व्यक्ति नवाब का उत्तराधिकारी होता था वही शाही संपत्ति का मालिक भी समझा जाता था। नवाब रजा अली खान के बाद उनके बेटे मुर्तजा अली खान को नवाब की गद्दी सौंपी गई। मगर 1971 में भारत सरकार ने प्रिवी पर्स खत्म कर दिए और इसके साथ ही नवाब की पदवी भी खत्म हो गई। नवाब की पदवी के समाप्त होने के बाद उनके भाई-बहनों में संपत्ति प्राप्त करने का विवाद शुरू हो गया। इसका मूल कारण यह था कि अंतिम नवाब रजा अली खान ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। लंबे समय तक संपत्ति का विवाद न्यायालयों में चलता रहा।

2002 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि भारत सरकार ने मुर्तजा अली खान को नवाब के अंतिम उत्तराधिकारी के रूप में माना था। इसलिए परम्परागत रूप से सारी संपत्ति पर उनका और उनके परिवारजनों का ही अधिकार है। अन्य वारिसों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि संपत्ति का विभाजन नवाब के 17 वारिसों में शरा के अनुसार होना चाहिए। नवाब परिवार देश की राजनीति में काफी सक्रिय रहा है। मुर्तजा अली खान और उनकी भाभी नूर बेगम लोकसभा के सदस्य रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस खानदान के कादिम अली खान ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था उसके अनुसार वे 55 करोड़ की जमीन और 76 लाख की जेवरात के मालिक हैं। जानकारों के अनुसार नवाब परिवार की कुल संपत्ति के मूल्य का अनुमान साढ़े सात सौ करोड़ से लेकर 1500 करोड़ तक आंका जाता है।

नागरिकता कानून के विरोध में गिरफ्तार लोगों को कानूनी सहायता

सियासत (4 जनवरी) के अनुसार "आंध्र प्रदेश के मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों से अपील की है कि विभिन्न बैंकों के खातों में ब्याज के रूप में उनके जो करोड़ों रुपये जमा हैं उनका इस्तेमाल उत्तर भारत में नागरिकता कानून और एनआरसी आंदोलन के दौरान में गिरफ्तार किए गए मुसलमानों की मदद के लिए किया जाए। समाचारपत्र ने कहा है कि

इस्लाम में क्योंकि ब्याज लेना हराम माना जाता है इसलिए मुसलमान बैंकों में जमा धनराशि पर मिलने वाले ब्याज को लेने का प्रयास नहीं करते और उन्हें मूल धन से अलग ही रखा जाता है। अब यह मौका आ गया है कि जो मुसलमान इस आंदोलन में पकड़े गए हैं या जेल में हैं उनकी सहायता के लिए बैंकों में जमा करोड़ों रुपये ब्याज की धनराशि का इस्तेमाल किया जाए। इस धनराशि से वकीलों की फीस और जमानत की रकम अदा की जा सकती है। राज्य के वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में यह घोषणा की है कि हाल के आंदोलन में जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें वक्फ बोर्ड की ओर से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मगर जेलों में बंद इन लोगों के लिए जमानतों की धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में मुसलमान ब्याज की जमा धनराशि का इस्तेमाल आंदोलन में पकड़े गए व्यक्तियों की जमानत के लिए कर सकते हैं।"

"समाचारपत्र ने देश भर के मुस्लिम खातेदारों से अनुरोध किया है कि वे अपने भाईयों की सहायता के लिए आगे आएं और विभिन्न बैंकों में जमा ब्याज की करोड़ों रुपये की धनराशि का एक फंड बनाएं जिससे जेलों में बंद मुसलमानों की कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसकी शुरुआत हैदराबाद नगर में विभिन्न बैंकों में जमा मुसलमानों के हजारों खातों की ब्याज धनराशि से हो सकती है।"

"जमीयत उलेमा के अरशद मदनी ने मुंबई में एक डिफेंस कमेटी बना रखी है जो आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए मुसलमानों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है और जिन परिवारों में कमाने वाला अन्य व्यक्ति नहीं होता उन्हें गुजारे की धनराशि भी दी जाती है। गत वर्ष इस कमेटी के प्रयासों से 590 व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष गुलजार आजमी का दावा है कि उनकी कमेटी के प्रयासों से सैकड़ों बेगुनाह जेल जाने से बच गए हैं।"

कश्मीर के मामले पर इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी

साप्ताहिक नई दुनिया (13 जनवरी) ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर पर इस्लामिक देशों के सहयोग संगठन (ओआईसी) की जो बैठक तुरंत बुलाने की घोषणा की थी उस मुद्दे पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। अब इस मुद्दे पर विदेश मंत्रियों का सम्मेलन तीन माह बाद यानि अप्रैल में होगा। अजीब बात है कि पाकिस्तान तथ्यों पर पर्दा डालकर ऐसा प्रचार कर रहा है जैसे उसने कोई बड़ी बाजी जीत ली हो। जबकि हकीकत यह है कि ओआईसी ने पाकिस्तान के साथ एक और भोंडा मजाक किया है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया भर के रूख से गहरी निराशा हुई है इसलिए अब उसे अपनी इज्जत और साख को बचाना सबसे कठिन काम बन गया है। इस मामले पर सऊदी अरब ने भारत का लगभग समर्थन ही किया है। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में उसे इस मुद्दे पर केवल दो देशों तुर्की और मलेशिया का ही समर्थन प्राप्त हुआ। इन दोनों देशों ने पिछले महीने मलेशिया में इस्लामिक देशों का एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें पाकिस्तान ने अंतिम क्षणों में भाग लेने से इनकार कर दिया। यह फैसला पाकिस्तान ने सऊदी अरब के दबाव में किया था। इसके बाद इस्लामिक जगत इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पर्दे के पीछे हुई सौदेबाजी की कहानी दुनिया के सामने आएगी। अब पाकिस्तान ने अपनी इज्जत और साख बचाने के लिए ओआईसी का सम्मेलन बुलाने की नौटंकी की है। हालांकि सब जानते हैं कि इसमें कुछ होना नहीं है। क्योंकि सऊदी अरब अपने आप को इस मामले से अलग रखना चाह रहा है।"

"पाकिस्तानी अखबारों ने दावा किया है कि सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने कश्मीर पर ओआईसी का अधिवेशन बुलाने की पुष्टि की है। इस

अधिवेशन में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इंडोनेशिया और अन्य देशों के भाग लेने की सम्भावना है। अधिवेशन इस्लामाबाद में होगा। अधिवेशन के एजेंडे में कश्मीर और नागरिकता संशोधन कानून पर चर्चा की सम्भावना है। सऊदी अरब ने मलेशिया में हुए सम्मेलन के बाद इस्लामिक देशों में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ओआईसी को सक्रिय करने का निर्णय किया है। बताया जाता है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल सउद ने हाल ही में पाकिस्तान के दौरों के दौरान इमरान खान को इस मामले में विश्वास में लिया था। मलेशिया कांफ्रेंस में **पाकिस्तान द्वारा भाग न लेने पर टिप्पणी करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा था कि आर्थिक दबाव के कारण पाकिस्तान ने मलेशिया के सम्मेलन में भाग नहीं लिया। सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तान को यह धमकी दी थी कि अगर उसने** इस सम्मेलन में भाग लिया तो सऊदी अरब में काम करने वाले 40 लाख पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया जाएगा और उनकी जगह बांग्लादेश के नागरिकों को भर्ती किया जाएगा।"

"पाकिस्तान का कहना था कि मलेशिया में होने वाले सम्मेलन में उसने इसलिए भाग नहीं लिया ताकि इस्लामी जगत को एकजुट रखा जाए। मगर पाकिस्तान का भांडा एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ही चौराहे पर फोड़ दिया। उसने कहा कि जिन लोगों ने हमारे स्टेट बैंक में अरबों डॉलर जमा करके हमारी विदेशी पूंजी के भंडार की वृद्धि में योगदान दिया है उनकी इच्छा का पालन करते हुए पाकिस्तान इस सम्मेलन से अलग रहा है। हैरानी तो इस बात का है कि पाकिस्तान की मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस मामले को पाकिस्तान की जीत के रूप में पेश कर रहा है। प्रचार यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान के महत्व को सामने रखते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री सबसे पहले पाकिस्तान आए। सवाल यह पैदा होता है कि अगर ओआईसी का सम्मेलन अप्रैल महीने में आयोजित होता है तो सऊदी अरब इस बैठक में क्या संदेश देगा? क्या वह पाकिस्तान के पक्ष में आवाज उठा पाएगा? सवाल यह है कि ओआईसी अब तक क्या कर रही है? सब जानते हैं कि सऊदी अरब के साथ भारत के आर्थिक सम्बन्ध इतने सुदृढ़ हो गए हैं कि उसकी नजर में पाकिस्तान का कोई महत्व ही नहीं रहा है।"

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में चार मुसलमान

जदीद मरकज (5 जनवरी) के अनुसार "महाराष्ट्र में शिवसेना की नेतृत्व वाली उद्धव ठाकरे सरकार में चार मुसलमानों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ शिवसेना ने भी अपने इकलौते मुस्लिम विधायक को मंत्री बनाया है। ठाकरे सरकार में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे से नवाब मलिक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उन्हें शरद पवार का विश्वस्त माना जाता है। वे अनुशक्ति नगर विधानसभा सीट से विजयी हुए हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। पांचवी बार वे विधायक चुने गए हैं। इसके पहले वे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। वे मुंबई प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इनके अतिरिक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस के कोटे से हसन मुशरिफ को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वे कोल्हापुर जिले के कागल विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। वे इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। कोल्हापुर में उनकी टक्कर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार से थी जो कि हार गया।"

"कांग्रेस के कोटे से असलम शेख मंत्री बनाए गए हैं। वे मलाड पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस से वे लगातार तीन बार विधायक बने हैं। कांग्रेस से महाराष्ट्र में 44 विधायक विजयी हुए हैं जिनमें से तीन मुसलमान हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना ने भी पहली बार अपने कोटे से अब्दुल सत्तार को मंत्री बनाया है। सत्तार चुनाव से पूर्व कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए थे। सत्तार औरंगाबाद क्षेत्र से शिवसेना के टिकट पर चुने गए हैं। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में 10 मुस्लिम विधायक विजयी हुए हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर डॉ. फारूक शाह धुले से और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी मालेगांव से जीते हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी दो मुसलमान विजयी रहे हैं। इनमें से अबू आसिम आजमी और रईस कासिम शेख शामिल हैं कांग्रेस के टिकट पर तीन मुस्लिम उम्मीदवार विजय हुए हैं। इनमें मुंबा देवी से अमीन पटेल, बांद्रा ईस्ट से जिशान बाबा सिद्दीकी और मलाड से असलम शेख जीते हैं।"

अखबार-ए-मशरिक (5 जनवरी) के अनुसार "कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने के कारण नाराज शिवसेना के अब्दुल सत्तार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा है कि आशा है कि वे अपना त्यागपत्र वापस ले लेंगे।"

अयोध्या में मस्जिद के लिए पांच वैकल्पिक स्थान

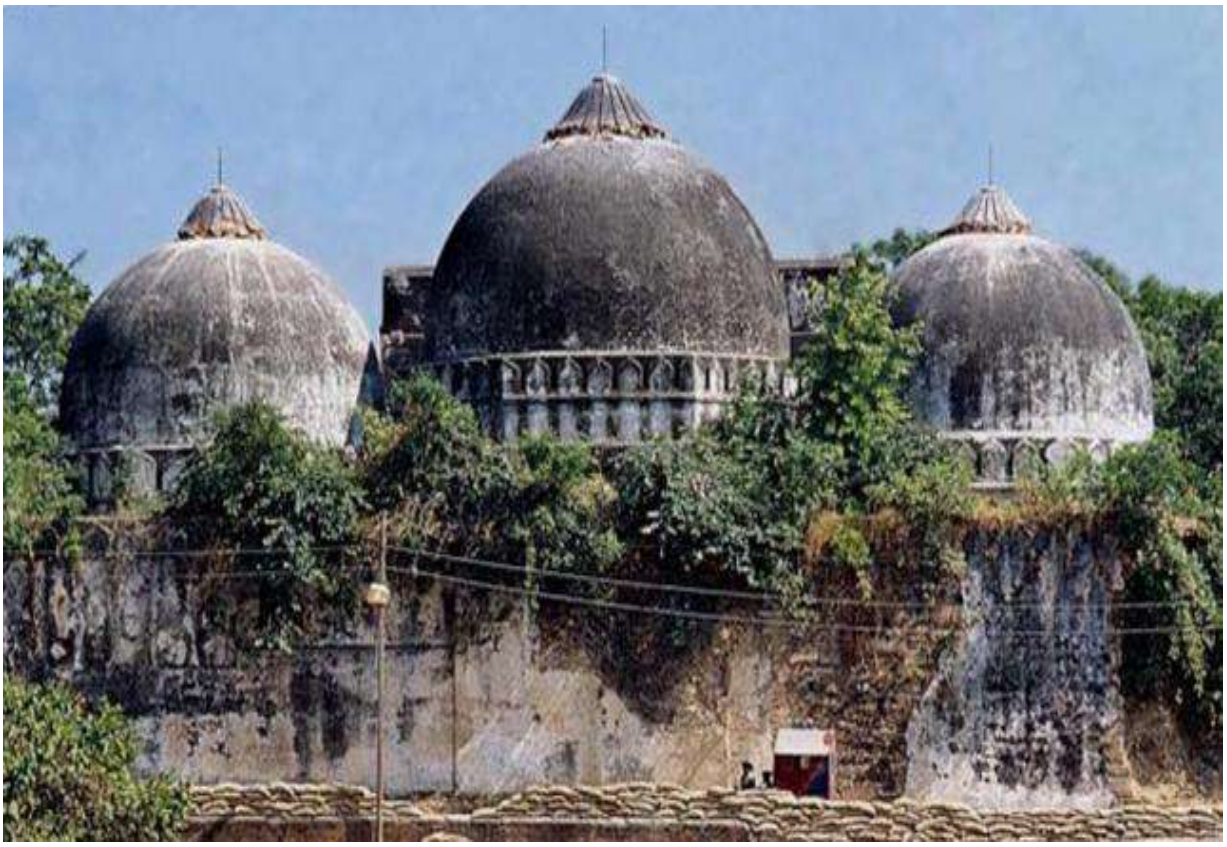

सियासत (2 जनवरी) के अनुसार "सर्वोच्च न्यायालय ने मुसलमानों को मस्जिद के निर्माण के लिए वैकल्पिक जगह देने का जो निर्देश दिया है उसे देखते हुए सरकार ने अयोध्या में पांच वैकल्पिक स्थानों की तलाश की है जहां पर मुसलमान अपनी मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। यह स्थान अयोध्या, फैजाबाद रोड, अयोध्या बस्ती रोड, अयोध्या सुल्तानपुर रोड और अयोध्या गोरखपुर रोड पर स्थित है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा योगी सरकार ने इन पांच जगहों को चिन्हित किया है। ये सभी चिन्हित स्थान पंच कोसी क्षेत्र से बाहर हैं।"

"पंच कोसी परिक्रमा का क्षेत्र 15 किलोमीटर है जिसे अयोध्या का पवित्र स्थान माना जाता है और योगी सरकार ने इस क्षेत्र से बाहर मस्जिद के निर्माण के लिए जगह देने का निर्णय किया है। जिन गांवों में वैकल्पिक जगह देने का प्रबंध किया गया हैं उनमें मल्लिकपुर, मिर्जापुर, समसुद्दीनपुर और चांदपुर शामिल हैं। ये सभी गांव अयोध्या से प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण जिलों से जोड़ने वाली सड़कों पर स्थित है। अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि इनमें से कौन सी जगह मस्जिद के निर्माण के लिए मुसलमानों को दी जाएगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के बदले में वैकल्पिक स्थान लेने से इनकार कर दिया है। इसी तरह से शियाओं ने भी वैकल्पिक स्थान लेने के लिए हामी नहीं भरी है। मुसलमान विद्वानों का कथन है कि इस्लाम के अनुसार जिस स्थान पर एक बार मस्जिद का निर्माण हो जाता है उस स्थान को न तो बेचा जा सकता है और न ही उसके बदले में कोई जगह ली जा सकती है। यही कारण है कि अधिकांश मुस्लिम संगठन मस्जिद के बदले में कोई भूमि या उसकी कीमत लेने के लिए तैयार नहीं हैं।"

बोगस लाइसेंस का मकड़जाल

मुंबई उर्दू न्यूज (31 दिसम्बर) का कहना है कि "सीबीआई के अनुसार सभी निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने अस्त्र-शस्त्रों के दो लाख बोगस लाइसेंस जारी किए हैं। इस गिरोह की तलाश में जांच एजेंसी ने दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापे मारे। बताया जाता है कि इन बोगस लाइसेंसों को एक पूर्व जिलाधिकारी ने जारी किया था जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुका है। जिन अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गए उनमें राजीव रंजन, आशा मुदगिल, इतरत हुसैन, सलीम मोहम्मद, मोहम्मद जावेद खान और जहांगीर अहमद मीर के नाम बताए जाते हैं। ये अधिकारी जब कुपवाड़ा, बारामुला, उधमपुर, किश्तवाड़, राजौरी और डोडा जिलों में नियुक्त थे तो उन्होंने यह लाइसेंस जारी किए थे। राजस्थान पुलिस की सिफारिश पर यह मामला दर्ज किया गया है। आरोप यह है कि 2012 से लेकर 2016 तक जम्मू-कश्मीर के डोडा, रामवन और उधमपुर से डेढ़ लाख से अधिक लाइसेंस जारी किए गए थे।"

"जांच के अनुसार जम्मू-कश्मीर में अब तक चार लाख से अधिक लाइसेंस जारी करने का पता चला है जिनमें से दो लाख फर्जी बताए जाते हैं। राजस्थान पुलिस इस मामले में कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गुड़गांव से एक आईएस अधिकारी के भाई को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने इस सम्बन्ध में चालीस लाख रुपये भी जब्त किए हैं। बताया जाता है कि ये फर्जी लाइसेंस एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अधिकारियों के नाम जारी किए गए थे। अब केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस घोटाले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हवाले कर दी है। अभी तक हुई जांच के अनुसार इस गिरोह के सम्पर्क दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि अनेक राज्यों में फैले हुए हैं। बताया जाता है कि एक मोटी रकम दलाल को देने के बाद सभी नियमों को ताक पर रखकर फर्जी लाइसेंस जारी कर दिया जाता था। एक उच्चाधिकारी के अनुसार इस घोटाले में अनेक बड़े अधिकारियों के भी फंसने की सम्भावना है।"

ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पथराव

"जहां तक ननकाना साहिब का संबंध है वह गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है इसलिए वह दुनिया भर के सिखों के लिए पवित्र स्थान है। हिन्दुस्तान में इसकी जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शशि थरूर और गुलाम नबी आजाद ने **पाकिस्तान सरकार से मांग की कि गुरुद्वारे को संरक्षण प्रदान** करना चाहिए। केन्द्रीय मंत्री और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है और ननकाना साहिब के गुरुद्वारे पर हुए हमले ने इसके भयंकर चेहरे को उजागर कर दिया है। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास पर सिखों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस घटना की निंदा की। गृह मंत्रालय ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इस घटना की निंदा की और पाकिस्तान सरकार से मांग की कि वह इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे और वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करे। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि प्रदर्शन का जो वीडियो वायरल हुआ है वह फर्जी है और गुरुद्वारे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा और पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि दो मुस्लिम गुटों में झगड़ा हुआ था। इसका कारण चाय की दुकान पर भुगतान का था। जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुद्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इस संदर्भ मे जो भी दावे किये जा रहे हैं वह शरारतपूर्ण है।"

साप्ताहिक नई दुनिया (13 जनवरी) के अनुसार "पाकिस्तान के नगर ननकाना साहिब में गुरुद्वारे के बाहर हुए उग्र प्रदर्शन और पथराव के कारण सारी दुनिया के सिखों में नाराजगी फैल गई है। इस घटना के खिलाफ भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के कारण ही पाकिस्तान को इस प्रदर्शन के आयोजक इमरान चिश्ती को आतंक निरोधक कानून के कारण गिरफ्तार करना पड़ा है। पिछले वर्ष जब गुरुद्वारा के एक ग्रंथी की लड़की का अपहरण करके जबरन उसका निकाह एक मुसलमान से करवा दिया गया था। इस पर पाकिस्तान में काफी हंगामा हुआ मगर बाद में न्यायालय में इस लड़की ने यह बयान दिया कि यह विवाह उसकी मर्जी से हुआ था। इसके बाद इस लड़की को उसके पति के हवाले कर दिया गया। हाल ही में जब यह लड़की अपने परिवार से मिलने के लिए ननकाना साहिब आई तो उसने पुलिस में एक दूसरा बयान दिया कि **उसका जबरन अपहरण करके उससे निकाह किया गया है। इस पर पुलिस ने इस लड़की के पति को गिरफ्तार कर लिया।** लड़की अभी सरकारी संरक्षण गृह में है। लड़की के पति और उसके समर्थकों ने ग्रंथी के घर पर पथराव किया, जो गुरुद्वारे के भीतर ही रहता है। उन्होंने कहा कि वे इस गुरुद्वारे को गिराकर इस स्थान पर मस्जिद बनाएंगे और ननकाना साहिब का नाम बदलकर गुलाम मुस्तफा किया जाएगा।"

टिप्पणी: इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस घटना से पाकिस्तान सरकार के उस मंसूबे को भारी झटका लगा है जिसके तहत वह भारत में खालिस्तानी उग्रवाद

की ज्वाला को भड़काने का प्रयास कर रहा था। पाकिस्तान सरकार का शुरू से ही यह प्रयास रहा है कि भारतीय समाज की एकता को तार-तार किया जाए। इसलिए वह सिखों को शुरू से ही हिन्दुओं के खिलाफ भड़काता आ रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान की कठपुतलियां विश्व भर में यह प्रचार कर रही हैं कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं हैं और हिन्दू समाज उनके अस्तित्व को खत्म करना चाहता है। हालांकि हकीकत यह है कि हिन्दू-सिख प्रारम्भ से ही एकजुट रहे हैं।

पंजाब में हिन्दुओं और सिखों के बीच शताब्दियों से रोटी-बेटी का नाता चला आ रहा है। पवित्र गुरुद्वारों में जो श्रद्धालु श्रद्धा सुमन भेंट करने आते हैं उनमें 90 प्रतिशत हिन्दू समाज से संबंधित होते हैं। हरिद्वार हो या वैष्णो देवी का मंदिर सभी जगह हिन्दू श्रद्धालुओं के साथ-साथ सिख भी भारी संख्या में दिखाई देते हैं। यह जरूर है कि पाकिस्तान को खंडित करने और बांग्लादेश के निर्माण का बदला लेने के लिए पाकिस्तान अपने कुछ कठपुतली सिखों के सहारे सिखों को हिन्दुओं के खिलाफ भड़का रहा है। इमरान खान के सत्ता में आने के बाद इस तरह की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। यह सर्वविदित है कि विदेशों में भारत सरकार के खिलाफ जिन प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है उनके पीछे पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई का हाथ होता है और वह खुले हाथ से भारत विरोधी तत्वों को धन बांटती है। हाल ही में पाकिस्तान ने एक नया दांव खेला और उसने गुरु नानक की समाधि पर 55 एकड़ भूमि में करतारपुर गुरुद्वारा बना डाला। करतारपुर भारतीय सीमा से दस किलोमीटर दूर है। इस जगह पर गुरु नानक देव जी ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे और वहीं उनका निधन हुआ था।

विश्व भर के सिखों में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया और यह मांग की कि भारत सरकार को सिख श्रद्धालुओं को बिना पासपोर्ट और वीजा के गुरु नानक देव जी के इस गुरुद्वारे के दर्शन करने की सुविधा दी जाए। भारत सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि सिर्फ पासपोर्टधारी ही करतारपुर गुरुद्वारा का दर्शन कर सकेंगे। पाकिस्तान सरकार इस गुरुद्वारे की आड़ में दुनिया भर में फैले सिखों में अपने पैर पसारने का प्रयास कर रही है। सिखों के हमदर्दी का दावा करने वाली पाकिस्तान सरकार विदेशी सिखों से इस गुरुद्वारा के दर्शन के लिए मोटी धनराशि फीस के रूप में वसूलती है। भारतीय गुप्तचर एजेंसियों के अनुसार जो भारतीय सिख यात्री करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन के लिए जाते हैं उनमें पाकिस्तानी सिख खालिस्तान का प्रचार करते हैं और उन्हें देशद्रोह के लिए भड़काते हैं।

पाकिस्तान अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष औसतन 1100 अल्पसंख्यक लड़कियों का धर्मांतरण करके मुसलमान युवकों से उनका निकाह कराया जाता है। यह वह आकड़ें हैं जिन्हें पाकिस्तान सरकार स्वीकार करती है। हालांकि जमीनी हकीकत इससे भी बहुत भयंकर है। पाकिस्तान में तब्लीगी जमात पूरी तरह से सक्रिय है। सिंध के पीर गुलाम अली शाह ने डॉन समाचारपत्र के साथ वार्ता करते हुए यह स्वीकार किया है कि उनका मिशन ज्यादा से ज्यादा हिन्दू-सिख और ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण करके उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करना है। उन्होंने कहा कि तब्लीग इस्लाम का महत्वपूर्ण अंग है। हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि वे ज्यादा से ज्यादा गैर मुसलमानों को इस्लाम में परिवर्तित करें। जो यह कर्तव्य नहीं निभाता उसे कयामत के दिन अल्लाह मियां को जवाब देना होगा। पाकिस्तान में उत्पीड़न से तंग आकर हजारों हिन्दुओं और सिख परिवारों को अपने सम्मान और प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा है।

चीन में पांच लाख मुसलमान बच्चे परिवार से अलग

सियासत (30 दिसम्बर) ने आरोप लगाया है कि "चीन ने पांच लाख मुस्लिम बच्चों को उनके माता-पिता से अलग करके आवासीय स्कूलों में भेज दिया है और दस लाख उइगर, कजाक और अन्य मुस्लिम सम्प्रदायों से संबंधित लोगों को हिरासती केन्द्रों में रखा गया है। अब इस अभियान ने एक बड़ा रूप ले लिया है। मुस्लिम परिवारों के पांच लाख बच्चों को उनके माता-पिता से अलग करके बोर्डिंग स्कूलों में भेज दिया गया है। बच्चों को माता-पिता से मिलने की अनुमति नहीं है।"

पाकिस्तानी मॉडल का हत्यारा भाई सरकार के हवाले

सियासत (4 जनवरी) के अनुसार "सऊदी सरकार ने पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच के हत्यारे भाई को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है ताकि उसके खिलाफ हत्या के आरोप में पाकिस्तान में मुकदमा चलाया जा सके। 15 जुलाई, 2016 को इस व्यक्ति ने अपनी बहन की गला घोटकर हत्या कर दी थी। फौजिया आजम नामक यह महिला मॉडलिंग और सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थी और उसने अपना नाम कंदील बलोच रखा हुआ था। उसकी हरकतों के कारण उसके परिवारजन काफी परेशान थे। उसकी अश्लील गतिविधियों से उत्तेजित होकर उसके सगे भाई ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद वह पाकिस्तान से फरार हो गया था। इस मॉडल की हत्या ने पाकिस्तान भर में खलबली पैदा कर दी थी। बाद में पाकिस्तान सरकार को इस बात की जानकारी मिली थी कि वसीम नामक हत्यारा सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहा है।"

"पाकिस्तान सरकार ने सऊदी सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह इस हत्यारे को अपने देश से निष्कासित करके पाकिस्तान के हवाले कर दे ताकि उसके खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया जा सके। वसीम खान नामक इस हत्यारे ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बहन की हत्या इसलिए की थी ताकि खानदान को बदनामी से बचाया जा सके। वसीम खान को इस बात का दुख था कि कंदील बलोच की गतिविधियों के कारण उसके परिवार की सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है। उसे अपनी इस हरकत का कोई मलाल नहीं है। उसने पुलिस को बताया कि उसने जो कुछ किया वह सही किया है और किसी भी आत्मसम्मान वाले व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए था।"

चेकोस्लोवाकिया में मुस्लिम विरोधी अभियान

अखबार-ए-मशरिक (6 जनवरी) के अनुसार "चेकोस्लोवाकिया में मुसलमानों की जिहादी गतिविधियों के कारण वातावरण इस्लाम के खिलाफ हो रहा है। देश के सबसे बड़े नगर प्राग में एक मस्जिद पर इस्लाम विरोधी नारे लिखे गए हैं। स्थानीय पुलिस के अनुसार कुछ अज्ञात लोगों ने यह धमकी दी है कि अगर चेक गणराज्य में इस्लाम का प्रचार किया गया तो हम प्रचार करने वालों का सफाया कर देंगे। इस धमकी को देने वाले के बारे में पुलिस जांच कर रही है। अगर वे पकड़े गए तो उन्हें एक वर्ष की कैद हो सकती है। मुस्लिम सम्प्रदाय के एक नेता मुनीब हुसैन ने कहा कि यहां पर रहने वाले मुसलमानों को इंटरनेट पर भी ऐसी ही धमकियां दी जा रही हैं। चेकोस्लोवाकिया में मुसलमान बहुत कम हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या केवल 3300 है। हालांकि गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार इस देश में रहनेवाले मुसलमानों की संख्या 10,000 के करीब बताई जाती है। चेकोस्लोवाकिया की कुल जनसंख्या 1,10,000 है। हाल ही में यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले हमलों में वृद्धि हुई है। गत वर्ष जर्मनी में मुसलमानों के खिलाफ 800 आक्रमण हुए और 40 मस्जिदों को निशाना बनाया गया। सरकारी सूत्रों के अनुसार यूरोप में मुसलमानों का हाथ अनेक आतंकवादी घटनाओं में पाया गया है इसलिए उनके खिलाफ वातावरण खराब हुआ है।"

सूडान के अधिकारियों को फांसी

सियासत (1 जनवरी) के अनुसार "सूडान के एक न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले एक शिक्षक की हिरासत में मौत के सिलसिले में गुप्तचर विभाग के 29 अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। कहा जाता है कि इन अधिकारियों ने अल बशर के विरोधी को गिरफ्तारी के बाद इतना प्रताड़ित किया कि वह दम तोड़ गया। न्यायालयी फैसले के बाद एक अधिकारी ने बताया कि सूडान के इतिहास में इससे पूर्व इतनी बड़ी संख्या में कभी सरकारी अधिकारियों को फांसी की सजा नहीं दी गई है। जिन लोगों को सजा दी गई है वे इसके खिलाफ न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अध्यापक अहमद अल खैर पर यह आरोप था कि उनके इशारे पर राष्ट्रपति बशर के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इस पर गुप्तचर अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और हिरासत में उनकी मौत हो गई। सरकार ने यह दावा किया था कि उनकी मौत जहरीला खाना खाने से हुई है और उन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन बाद में उच्चस्तरीय जांच से यह सिद्ध हुआ कि गुप्तचर अधिकारियों ने उनका उत्पीड़न किया था जिसके कारण उन्होंने दम तोड़ दिया।"

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की तैयारियां

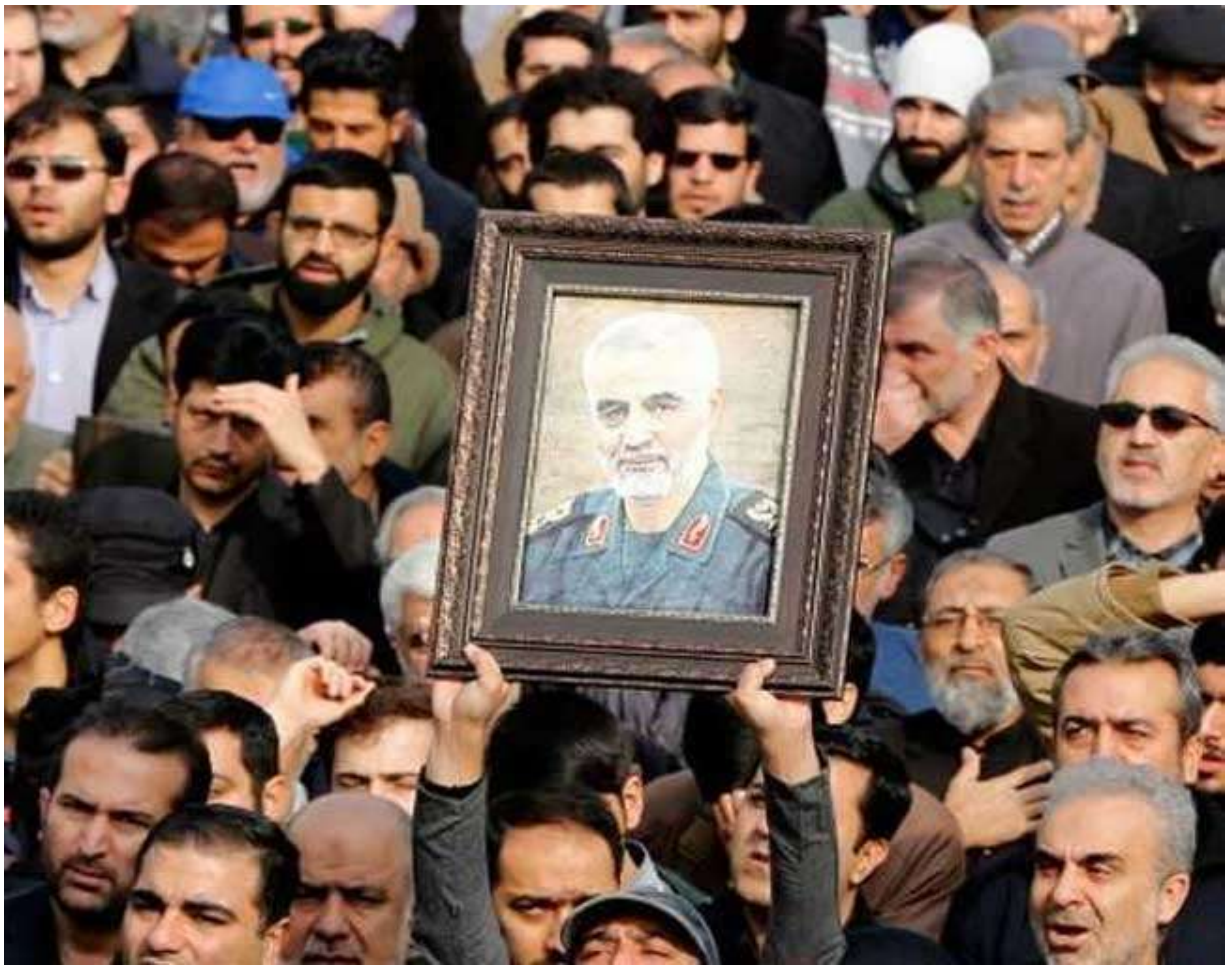

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को इस बार राष्ट्रपति पद के लिए पुनः चुनाव लड़ना है इसलिए उन्होंने अमेरिकी जनता के वोट प्राप्त करने के लिए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। उनके आदेश से ईरान के सबसे लोकप्रिय जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई है। इस हत्या का बदला लेने के लिए ईरान ने अमेरिकी सेनाओं पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। समाचारपत्रों का आरोप है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए विश्व को तीसरे युद्ध की ओर धकेल रहे हैं।

साप्ताहिक नई दुनिया (13 जनवरी) ने मुख्य पृष्ठ पर कासिम सुलेमानी का एक चित्र प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके साथ ही शीर्षक दिया है- 'ट्रम्प पागल हो गया, ईरान पर एटम बम गिराने की धमकी।' दूसरा शीर्षक है- 'ट्रम्प के हाथों कासिम सुलेमानी की कत्ल, अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत।'

अखबार-ए-मशरिक (9 जनवरी) का प्रमुख शीर्षक है- 'अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला, 80 अमेरिकी सैनिक मरे, जनरल सुलेमानी की मौत पर बदले की कार्रवाई, अमेरिकी राष्ट्रपति की कतर, जर्मनी और अन्य देशों के प्रमुखों से बातचीत।' इसके साथ ही एक अन्य समाचार भी प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि "तेहरान में यूक्रेन का एक विमान तबाह हो गया है जिसमें 180 लोग मारे

गए हैं। मरने वालों में 82 ईरानी भी शामिल हैं।"

इंकलाब (22 जनवरी) के अनुसार ईरान ने यह स्वीकार किया है कि "एक मिसाइल गलती से चल गई थी जिसके कारण यह विमान तबाह हो गया है।"

अखबार-ए-मशरिक (9 जनवरी) के अनुसार अमेरिका ने यह घोषणा कि "वह जबर्दस्त जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।"

इंकलाब (1 जनवरी) के अनुसार "इराक की राजधानी बगदाद में हजारों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया और उसको आग लगा दी। अमेरिका के निर्देश पर अमेरिकी दूतावास और अन्य स्टाफ को वहां से निकाल लिया गया है। प्रदर्शनकारी इराक और सीरिया की सीमा पर मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह पर अमरीकियों के हवाई हमले के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में कम-से-कम दो दर्जन लड़ाकू मारे गए। दो दशकों में यह पहला मौका है कि प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास तक पहुंचने में सफल हुए हैं। खास बात यह है कि अमेरिकी दूतावास के रास्ते में इराकी सेना की अनेक चौकियां हैं मगर इराकी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। अमेरिकी वायुसेना ने जिहादियों के ठिकाने पर हमले किए। ये हमले इराक स्थित अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हमले के जवाब में किए गए थे। प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास को बंद करने और इराक में रहने वाले अमेरिकी सैनिकों की वापसी की मांग कर रहे थे। पिछले दो महीने से इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। अब तक पांच सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।"

"**इंकलाब** के इसी अंक में प्रकाशित एक अन्य समाचार में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह आरोप लगाया है कि ईरान के इशारे पर बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। इस हमले में एक अमेरिकी अधिकारी मारा गया है और कई लोग जख्मी हो गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इराकी सरकार से मांग की कि अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इराक के नगर कुर्क में हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में अमेरिका ने इराक और सीरिया में हमले किए हैं। इराक सरकार ने अमेरिकी हमले में मारे गए इराकी मिलिशिया के वर्करों के शोक में देश भर में तीन दिन तक राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की है। इराकी प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके हमले कर रहा है।"

इंकलाब ने इसी अंक में अपने सम्पादकीय में आरोप लगाया है कि "अमेरिका इराक को तबाह करने की साजिश रच रहा है। 1990 से ही अमेरिका इराक को तबाह करने का प्रयास कर रहा है। 1991 के युद्ध में 50 हजार इराकी अमेरिका ने मार दिए थे। 2003 में सद्दाम की हत्या के बाद अमेरिका ने इराक पर अपनी सेना उतार दी थी और एक दशक में छह लाख इराकी नागरिक मारे जा चुके हैं। सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद अमेरिका ने इराक में कठपुतली लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया और अपनी कठपुतलियों को गद्दी पर बैठा दिया। अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सीआईए ने इराक में सुन्नी और शियाओं का संघर्ष शुरू कर दिया। मगर जब इसमें वह सफल नहीं हुआ तो अमेरिकी एजेंटों ने सामर्रा और कर्बला जैसे शिया तीर्थों पर हमले किए। अमेरिका के इशारे पर आईएसआईएस का गठन हुआ और इस्लामी खिलाफत की स्थापना करने की घोषणा कर दी गई।"

"हैरानी की बात यह है कि अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब और यूरोप के किसी देश ने यह नहीं पूछा कि इस खिलाफत के पास अति आधुनिक अस्त्र-शस्त्र कहां से आए हैं? दरअसल इस आतंकवादी संगठन की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि अमेरिका इराक में अपनी सेना को बनाए रखने के लिए कोई बहाना पेश कर सके। आईएसआईएस का सफाया होने के बाद यह दावा किया गया कि इसमें ईरानी सरकार का हाथ है। अमेरिका इराक को अपनी संपत्ति समझता है इसलिए वह इसमें ईरान का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहता। अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। चार महीने से इराकी जनता बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अमेरिका ने इसका रूख ईरान की ओर मोड़ने का प्रयास किया और इसलिए नजफ और कर्बला में स्थित ईरानी

दूतावासों को निशाना बनाया गया। अब अमेरिका किसी तरह से फिर इराक को जंग की ज्वाला में धकेलना चाहता है।"

इंकलाब (6 जनवरी) के अनुसार "अमेरिका को इराक में जबर्दस्त झटका लगा है। ईरान के मुख्य सेनाध्यक्ष कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद इराकी संसद के एक विशेष अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निर्णय किया गया है कि अमेरिका के साथ की गई सुरक्षा संधि को समाप्त कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त इराकी संसद ने यह भी फैसला किया है कि इराक में जो भी अमेरिकी या विदेशी सैनिक हैं उन्हें फौरन देश से निकाल दिया जाए और किसी भी उद्देश्य के लिए विदेशी सैनिकों को इराक की भूमि, वायु सीमा और समुद्री सीमा के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाए। इराकी संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी ने कहा कि देश से विदेशी सैनिकों को अति शीघ्र निकालने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या को राजनीतिक हत्या बताया। उन्होंने कहा कि हालांकि इराक में विदेशी सैनिक हमारी मर्जी से मौजूद हैं मगर जिस तरह से इराकी सीमा के भीतर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की गई है उसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता। इस समय इराक में अमेरिका के पांच हजार सैनिक मौजूद हैं। मगर अब उन्हें यहां से जाना होगा। हालांकि इसके कारण कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इराकी संसद के 170 सांसदों ने इराक से अमेरिकी सांसदों को निकालने के फैसले पर हस्ताक्षर किए हैं।"

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (6 जनवरी) के अनुसार "अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने किसी भी अमेरिकी नागरिक या अमेरिकी संपत्ति पर हमला किया तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान इसे चेतावनी के रूप में समझे। अगर उसने एक भी अमेरिकी पर हमला किया तो हम 52 ईरानी स्थानों को अपना निशाना बनाएंगे। ये सभी केन्द्र ईरान की संस्कृति के केन्द्र हैं। ईरान हमें धमकियां दे रहा है। मगर उससे हम निपटना जानते हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के बारे में कहा है कि उसने तो जंग की घोषणा कर दी है। ईरान की ऐतिहासिक मस्जिद पर लाल रंग का झंडा लहरा दिया गया है। ईरान सरकार के सरकारी टेलीविजन से बार-बार इस झंडे के फोटो को प्रसारित किया गया। प्राचीन फारसी परम्पराओं के अनुसार जब इस मस्जिद पर लाल रंग का झंडा लहराया जाता है तो उसका अर्थ जंग शुरू करना या बदला लेना होता है। लाउडस्पीकर पर अल्लाह से यह दुआ मांगते हुए सुना गया है कि हे अल्लाह अपने संरक्षक को फिर से दुनिया में भेजो। इसे पैगम्बर महदी के पुनः प्रकट होने से जोड़ा जा रहा है। इस्लामी परम्पराओं के अनुसार कयामत होने से पूर्व इमाम महदी प्रकट होंगे और वे बुराई का खात्मा कर देंगे। हालात को बिगड़ते देखकर पहले संयुक्त राष्ट्र संघ और अब यूरोपियन यूनियन के देशों ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वे सब्र से काम लें और तनाव को बढ़ने से रोकें।"

"चीन के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह फौजी शक्ति का गलत इस्तेमाल न करे। चीनी विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री से इस संदर्भ में टेलीफोन पर वार्ता भी की है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अमेरिका की युद्ध की धमकियों को गम्भीरता से लेते हैं। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि स्थिति न बिगड़े। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इस संदर्भ में रूस और तुर्की के राष्ट्रपति से अलग अलग वार्ता की है। ब्रिटेन ने कहा है कि कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद जो स्थिति बन रही है उसे सम्भालने की जरूरत है। संघर्ष ब्रिटेन के हित में नहीं है। सीरिया के विदेश मंत्री ने इराक और ईरान से संवेदना प्रकट की है और कहा है कि इराक में जो अस्थिरता पैदा हुई है उसके लिए अमेरिका जिम्मेवार है। सैनिक आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के पास हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों की संख्या 10,000 है जबकि ईरान के पास सिर्फ 512 ही जहाज और हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिका के पास 12,81,000 हजार सैनिक हैं जबकि ईरान के पास 5,23,000 हजार सैनिक हैं। अमेरिका के पास 48,422 टैंक और तोपें हैं जबकि ईरान के पास इनकी संख्या 8,577 है। जहां तक जलपोतों और पनडुब्बियों का संबंध है अमेरिका के पास इनकी संख्या 515 है। जबकि ईरान के पास 398 है। दोनों देशों की रक्षा बजट में भी भारी अंतर है। अमेरिका का रक्षा बजट 716 अरब डॉलर का है जबकि ईरान

का बजट सिर्फ 6.3 अरब डॉलर है।"

"इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार कासिम सुलेमानी का शव अंतिम संस्कार के लिए इराक से ईरान लाया गया और उन्हें उनके पैतृक नगर केर्मान में दफन किया जा रहा है। एक अन्य समाचार के अनुसार इराक ने तीन दिनों तक राष्ट्रव्यापी शोक मनाने की घोषणा की है। एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिका ने दो हजार सैनिकों को मध्य-पूर्व भेज दिया है। बताया जाता है कि मोरक्को में सैनिक अभ्यास में भाग लेने वाले अमेरिकी सैनिकों को भी इराक भेजा जा रहा है। मोरक्को में होने वाले सैनिक अभ्यास रद्द कर दिए गए हैं।"

अखबार-ए-मशरिक (5 जनवरी) के अनुसार "अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उनके देश ने विश्व के सबसे प्रमुख आतंकवादी कासिम सुलेमानी का खात्मा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम की हत्या करने का उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया था। उन्होंने दावा किया कि सुलेमानी ने अमेरिका और विश्व के अन्य देशों में तबाही मचाने की योजना बना रखी थी। इसलिए विश्व को बचाने के लिए सुलेमानी का खात्मा जरूरी था। उन्होंने दावा किया कि वे विश्व युद्ध छेड़ना नहीं चाहते बल्कि उसे रोकना चाहते हैं। इसलिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की सैकड़ों हत्याओं में सुलेमानी का हाथ है।"

अखबार-ए-मशरिक (5 जनवरी) ने अपने सम्पादकीय में जनरल सुलेमानी की हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि "राष्ट्रपति की कुर्सी पाने के लिए ट्रम्प ने यह **खेल खेला है। ट्रम्प के विरोधी उम्मीदवार ने कहा है कि ट्रम्प ने बारूद के ढेर में आग लगाने का काम किया है। पकिस्तान** ने यह भय व्यक्त किया है कि जनरल सुलेमानी की हत्या के कारण इस्लामिक राज्यों के गुट का वजूद खतरे में पड़ सकता है। यूरोपीयन यूनियन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका की इस हरकत से हिंसा भड़क सकती है और आतंकवाद पुनः सिर उठा सकता है। ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने कहा कि सुलेमानी की मौत से उसका मिशन खत्म नहीं हो जाता। अमेरिकी समाचारपत्र अटलांटिक ने कहा है नए साल में ट्रम्प ने दुनिया भर को जंगी हिस्ट्रीया में धकेल दिया है।"

इत्तेमाद (3 जनवरी) ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि "ईरान और अमेरिका में दिन-प्रतिदिन तनाव बढ़ रहा है और इसके लिए अमेरिका पूरी तरह से जिम्मेवार है। हाल ही में जिस तरह से सुलेमानी की हत्या की गई है उससे यह साफ है कि अमेरिका इस्लामिक देशों को जंग में धकेलना चाहता है। समाचारपत्र ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे एकजुट होकर इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला करें।"

इंकलाब (8 जनवरी) के अनुसार "तेहरान में कासिम सुलेमानी के जनाजे में हुई भगदड़ के कारण 50 से अधिक लोग मर गए हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह स्पष्ट किया है कि सुलेमानी पर हुए हमले में इजरायल का कोई हाथ नहीं है। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे विदेशियों के हमले का सामना करने के लिए एकजुट हो जाएं। अगर मुसलमान **एकजुट नहीं हुए तो कोई भी नहीं बचेगा। ईरान की मिलिशिया पासदाराने इंकलाब के प्रमुख जनरल हसन सलामी** ने घोषणा की है कि कासिम सुलेमानी के खून का ऐसा बदला लिया जाएगा जिसे दुनिया इतिहास में हमेशा याद रखेगी। उन्होंने कहा कि इराक और सीरिया में आईएसआईएस की जो हार हुई थी वह अमेरिका और उसके सहयोगियों की हार थी। क्योंकि अमेरिका ने इस संगठन को सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलटने के लिए बनाया था। उन्होंने कहा कि सुलेमानी आज भी जिंदा हैं और वे हमेशा जिन्दा रहेंगे। शहीद सुलेमानी अमेरिका के लिए हमेशा खतरा बने रहेंगे।"

"एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान की संसद ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और उससे सम्बन्धित सभी कम्पनियों और संस्थानों एवं उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को आतंकवादी घोषित करने का बिल पास कर दिया है। यह बिल ईरानी संसद के आपातकालीन अधिवेशन में सर्वसम्मति से पास हुआ है। इंकलाब में ही प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भाग लेने के लिए ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ को वीजा देने से इनकार कर दिया है।"

आतंकवाद के आरोप में 24 व्यक्तियों को सजा

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (1 जनवरी) के अनुसार "जॉर्डन के एक न्यायालय ने 24 व्यक्तियों को आतंकवादी हमलों की योजना बनाने के आरोप में 15-15 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इन पर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से संबंधित होने का आरोप है। इससे पूर्व अप्रैल 2019 में इसी संबंध में 17 व्यक्तियों को सजा सुनाई चुकी है। न्यायालय में पेश की गई चार्जशीट के अनुसार इस गिरोह ने जॉर्डन के टीवी चैनल, नाइट क्लब और गुप्तचर विभाग के मुख्यालय को बमों से उड़ाने की योजना तैयार की थी। पिछले तीन वर्ष में 150 से अधिक लोगों को जॉर्डन की विभिन्न अदालतें सजा सुना चुकी हैं।"

सोमालिया में बम धमाके से 76 मरे

इंकलाब (29 दिसम्बर) के अनुसार "सोमालिया की **राजधानी में एक बम धमाके में 76 लोग मारे गए और कई जख्मी हो गए। धमाके में कई वाहन नष्ट हो गए। सोमालिया** में इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल शबाब सक्रिय है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार मरने वालों में दो तुर्की नागरिक भी शामिल हैं। मरनेवालों में अधिकांश छात्र हैं। अल शबाब ने इस धमाके की जिम्मेवारी ली है। दो सप्ताह पूर्व अल शबाब ने नगर के एक होटल पर बम धमाके करके अनेक लोगों की हत्या कर दी थी। पिछले दो वर्षों में कार बम धमाके के कारण 512 लोग मारे जा चुके हैं।"

सऊदी अरब में अश्लील कपड़े पहनने के आरोप में 200 व्यक्ति गिरफ्तार

अखबार-ए-मशरिक (31 दिसम्बर) के अनुसार "सऊदी अरब में गत सप्ताह दो सौ से अधिक महिलाओं और पुरुषों को अश्लील लिबास पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए एक म्युजिक फेस्टिवल में महिलाओं से छेड़खानी के आरोप में 88 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने एक वर्ष पूर्व सऊदी अरब में जो उदारवादी अभियान चलाया था उसके बाद पहली बार इस तरह का क्रैक डाउन हुआ है। सऊदी पर्यटन विभाग ने यह परामर्श दिया है कि सऊदी अरब में आने वाले लोग टाइट लिबास न पहनें और न ही ऐसा लिबास पहनें जिससे उनका शरीर नग्न होता हो। विशेष रूप से उन्हें अपने कंधे और घुटनों को ढंकने वाला लिबास पहनना चाहिए।"

सैनिक स्कूल पर हमला

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (6 जनवरी) के अनुसार "लीबिया की राजधानी त्रिपोली में एक सैनिक स्कूल पर हुए हवाई हमले में कम-से-कम 30 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हो गए हैं। हमला उस वक्त हुआ जब कैडेट

परेड ग्राउंड में जमा थे। लीबिया के प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे घायलों के लिए अपना रक्तदान करें। लीबिया में पिछले एक वर्ष से गृहयुद्ध चल रहा है। विद्रोहियों की कमान खलीफा हफ्तर के हाथ में है। लीबिया में पूर्व राष्ट्रपति गद्दाफी की मौत के बाद वहां पर गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है।"

ईरान में विदेशी ऑयल टैंकर जब्त

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (1 जनवरी) के अनुसार "ईरान की मिलिशिया ने अरब की खाड़ी में एक विदेशी जहाज को पेट्रोल की तस्करी करने के आरोप में पकड़ा है। इस जहाज पर मलेशिया के 16 लोग सवार थे। यह छठा जहाज है जिसको ईरानी सेना ने जब्त किया है। इस जहाज पर 13 लाख लीटर पेट्रोल लदा हुआ था। इससे पूर्व में फिलीपींस का भी एक जहाज इसी आरोप में पकड़ा गया था।"

अमेरिका को भारत के शिया नेता की धमकी

इंकलाब (8 जनवरी) के अनुसार "ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के खिलाफ हिन्दुस्तान में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दिल्ली में अंजुमन हैदरी की ओर से अमेरिकी दूतावास पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया जिसमें हजारों मुसलमान शामिल हुए। वे अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। काफी प्रदर्शनकारियों के हाथ में मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीरें थीं। प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए शिया नेता मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान और इराक में स्थित शियाओं के पवित्र स्थानों पर कोई हमला किया तो फिर हिन्दुस्तान में एक भी अमेरिकी नागरिक को रहने नहीं दिया जाएगा। चाहे हमें उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। उन्होंने एबीपी न्यूज चैनल द्वारा कासिम सुलेमानी को आतंकवादी बताने की निंदा की और कहा कि यह न्यूज चैनल अमेरिका के पैसे पर चल रहा है। हम देश के मुसलमानों से अपील करते हैं कि वे इसका सम्पूर्ण बहिष्कार करें।"

"उन्होंने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ने जिसको भी अपना दोस्त बनाया है उसी को तबाह किया है। इसलिए भारत सरकार को सोचना चाहिए कि वह अमेरिका से बच कर रहे और ईरान व इराक से दोस्ती बढ़ाए। क्योंकि वहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा जिससे देश में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में सफलता मिलेगी। शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि इस समय नया शैतान अमेरिका है जिसके खिलाफ विश्व भर के मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। अंजुमन हैदरी के महामंत्री सैयद बहादुर अब्बास ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शनों का यह सिलसिला देश भर में फैल जाएगा। देश भर में अनेक स्थानों पर शिया मस्जिदों और इमामबाड़ों में विशेष मजलिसों का आयोजन किया गया जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी को श्रद्धांजलि दी गई।"

मुंबई में बकरे काटने पर प्रतिबंध

मुंबई उर्दू न्यूज (24 दिसम्बर) के अनुसार "अभी तक महाराष्ट्र में कसाई अपनी दुकानों में ही बकरों को काटकर उनका मांस बेचा करते थे। मगर अब दुकानदारों को यह अनुमति नहीं होगी। मुंबई नगर निगम ने इसके लिए जो स्थाई लाइसेंस जारी किए थे उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है। कसाई यह मुद्दा न्यायालय में ले गए थे। मगर न्यायालय ने बकरों को दुकानों में काटने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इन बकरों को देवनार की वधशाला में ही काटा जाए। देवनार के महाप्रबंधक योगेश सेठे ने बताया कि देवनार की पशु वधशाला में 18 हजार बकरे काटने की व्यवस्था है। इन्हें तीन शिफ्टों में बांटा जा सकता है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस पाबंदी के कारण मुंबई में मांस की मूल्यों में भारी वृद्धि होगी।" ■

बीबी को बंदरिया कहने पर जुर्माना

अखबार-ए-मशरिक (4 जनवरी) के अनुसार "संयुक्त अरब अमीरात में अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद बंदरिया के शीर्षक से उसकी फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले व्यक्ति को 20 हजार दिरहम का जुर्माना किया गया है। अरब मीडिया के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के एक नागरिक ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। इसके बाद पति ने अपनी पूर्व पत्नी का चित्र सोशल मीडिया पर शेयर किया और साथ ही शीर्षक में लिखा तुम बंदरिया हो और बंदरिया मेरे घर में नहीं रह सकती। मेरे घर से चली जाओ।"

"इस टिप्पणी के खिलाफ पत्नी ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। अदालत ने पति का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसे बीस हजार दिरहम क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि पति ने यह पोस्ट करके पत्नी की साख को क्षति पहुंचाई है। जबकि उस व्यक्ति का कहना था कि मैंने अपनी पूर्व पत्नी का अपमान नहीं किया और न ही ऐसा संदेश भेजा है जिससे उसका अपमान होता हो। सरकारी वकील ने पूर्व पति के वह सारे संदेश अदालत में पेश किए जिसमें उसने अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज की थी और उस पर बेहुदा आरोप लगाए थे।" ■

चारमीनार की लोकप्रियता

सियासत (1 जनवरी) के अनुसार "पिछले वर्ष 12 लाख से अधिक व्यक्तियों ने हैदराबाद की ऐतिहासिक चारमीनार को देखा और उसके उपरी मंजिल पर चढ़कर तस्वीरें खींची। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर दिन चार हजार व्यक्ति इस ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए आते हैं। अवकाश के दौरान इनकी संख्या बढ़कर पांच हजार तक पहुंच जाती है। पिछले वर्ष के दौरान एक लाख के लगभग विदेशी पर्यटकों ने इस स्मारक को देखा जिससे पुरातत्व विभाग को 33 लाख 42 हजार रुपये की आय हुई। सरकारी सूत्रों का दावा है कि इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी। सरकार इन दिनों चारमीनार की मरम्मत करवा रही है। पुरातत्व विभाग ने ऐतिहासिक मक्का मस्जिद की मरम्मत के लिए भी दस करोड़ रुपये अगले वर्ष खर्च करने का फैसला किया है।"

उत्तर प्रदेश में तीन तलाक का मुकदमा

अखबार-ए-मशरिक (5 जनवरी) के अनुसार "उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की एक महिला ने पुलिस में यह रपट दर्ज करवाई है कि उसके पति ने फोन करके उसे तीन तलाक दे दिया है। तीन बच्चों की मां इस महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके पति ने जबरन उसकी छोटी बहन से शादी कर ली। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके पति ने उसे टेलीफोन करके तीन तलाक दे दिया। मजेदार बात यह है कि उसकी बहन ने भी अपनी शिकायत में अपनी बहन का ही समर्थन किया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला सेल को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि 2009 में उसका विवाह बुलंदशहर के एक व्यक्ति से हुआ था। उससे

उसके तीन बच्चे भी हैं। पिछले वर्ष 30 जुलाई को वह उसकी छोटी बहन को बहला-फुसलाकर गाजियाबाद ले गया और वहां पर उससे कोर्ट मैरिज कर लिया। जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो पति ने उसे घर से निकाल दिया और उसके तीनों बच्चे उससे छीन लिए। बाद में उसकी बहन ने इस विवाह को रद्द करवा दिया। मगर इसके बावजूद आरोपी ने उसे और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी है।"

फर्जी आधर कार्ड बनाने पर रोहिंग्या गिरफ्तार

सियासत (6 जनवरी) के अनुसार "हैदराबाद की कंचन बाग पुलिस ने एक रोहिंग्या मुसलमान को जाली दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि 34 वर्षीय रहीमुल्लाह, निवासी बाबानगर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक एजेंट के सहयोग से आधार कार्ड प्राप्त किया था। जब पुलिस को यह सूचना मिली तो उसने उसके घर पर छापा मारकर उसके कब्जे से आधार कार्ड बरामद कर लिया। पुलिस ने रहीमुल्लाह को जेल भेज दिया है। कंचन बाग पुलिस थाना के इंचार्ज वेंकट रेड्डी ने बताया कि पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि हैदराबाद में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड बनाने वाला एक गिरोह सक्रिय है। पुलिस इस गिरोह का पता

लगा रही है। इसके साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या रहीमुल्लाह, उसकी पत्नी और बच्चों के कार्ड भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए हैं?"

विश्लेषण हेतु उर्दू समाचार-पत्रों की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार-ए-मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली
25. मुंबई उर्दू न्यूज़, मुंबई

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

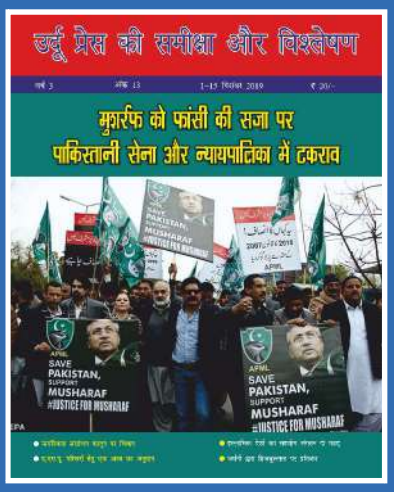

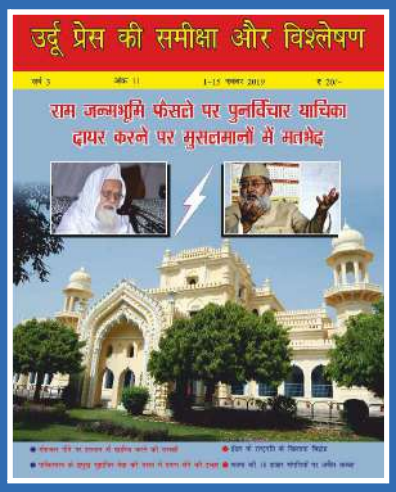

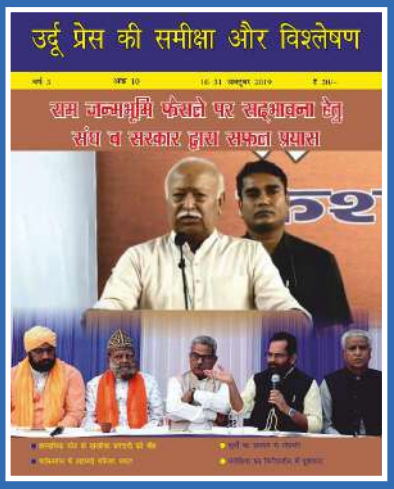

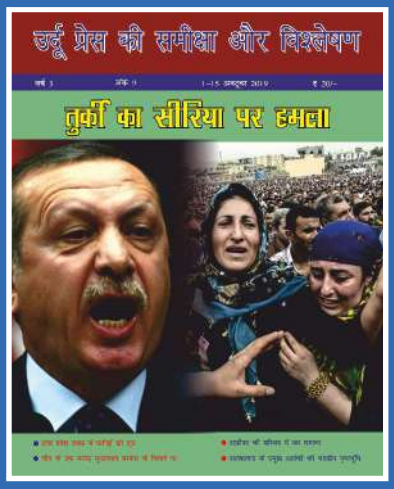

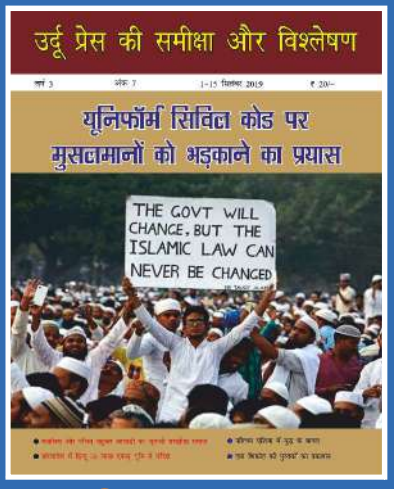

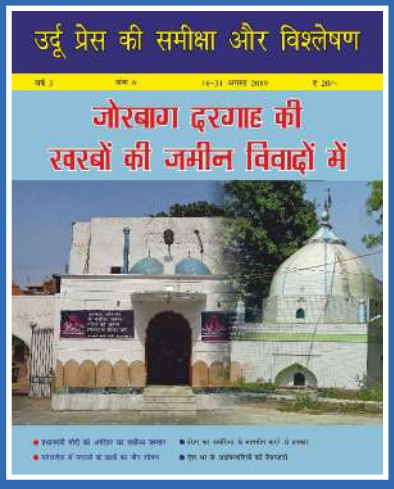

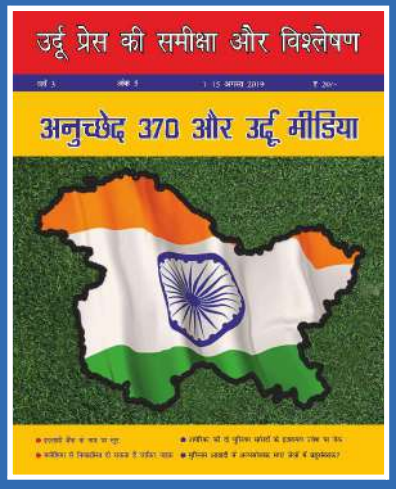

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
प्रदीपयेम जगत् सर्वम्
डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेलः info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com, वेबसाइटः www.ipf.org.in